

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section—3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 698]
No. 698]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 1996/अग्रहायण 8, 1918
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 1996/AGRAHAYANA 8, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1996

आयकर

का. आ. 836 (अ).—चूंकि आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित करार निष्पादित हो गया है;

और चूंकि उपर्युक्त करार उक्त करार के अनुच्छेद 28 के अनुसार दोनों ही संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अक्टूबर, 1996 के 26 वें दिन को एक दूसरे के संबंध में प्रवृत्त किया गया;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए

भारत गणराज्य

और

जर्मन संघीय गणराज्य

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और

जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार,

आय तथा पूंजी संबंधी करों पर दोहरे कराधान के परिहार तथा अपने पारस्परिक आर्थिक संबंधों के संवर्धन हेतु एक करार निष्पन्न करना चाहती है;

अतः अब एतद्वारा नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद—1**वैयक्तिक क्षेत्र**

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद—2**करार के अंतर्गत आने वाले कर**

1. यह करार, आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में लागू होगा जो किसी संविदाकारी राज्य की ओर से किसी प्रदेश अथवा किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए जाएं, भले ही उन्हें लगाए जाने की प्रक्रिया कैसी भी हो।

2. सकल आय, संपूर्ण पूंजी अथवा आय अथवा पूंजी के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय तथा पूंजी पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाषों और वेतन-पत्रक पर लगाए गए कर भी शामिल हैं।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषतया इस प्रकार हैं :

(क) भारत गणराज्य में :

आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है (आइनकॉमनश्टॉयर आइनश्लीश्लीख डाराउफ एंटफालेन्डर त्सूजात्सश्टॉयर्न) और धन कर (फेर्मोएगन्श्टॉयर);

(जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है),

(ख) जर्मन संघीय गणराज्य में :

आइनकॉमनश्टॉयर (आयकर) कोएर्परशाफ्टश्टॉयर (निगम कर); फेर्मोएगन्श्टॉयर (पूंजी कर) और गेवेबैश्टॉयर (व्यापारिक कर);

(जिन्हें इसके बाद "जर्मन कर" कहा गया है)।

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद - 3**सामान्य परिभाषाएं**

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "भारत का गणराज्य" पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्य क्षेत्र तथा उसमें शामिल क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र। इस करार के प्रयोजनों के लिए, इस पद में कोई ऐसा अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल होगा जिस पर भारतीय कानून के अनुसार तथा विशेषतया समुद्र कानून के संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय में यथा-निर्धारित अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के गणराज्य के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों;

(ख) "जर्मन संघीय गणराज्य" पद से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिस पर जर्मन संघीय गणराज्य के कर कानून लागू होते हैं जिसमें समुद्र क्षेत्र,

उसका वह उप-भाग और क्षेत्रीय समुद्र के समीप का उपरिर्वाही जल कॉलम भी शामिल है जिस पर जर्मन संघीय गणराज्य का, अन्तरराष्ट्रीय कानून तथा इसके राष्ट्रीय विधान के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार हों;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से यथा संदर्भ जर्मन संघीय गणराज्य अथवा भारत गणराज्य अभिप्रेत हैं;

(घ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी और कोई भी अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत कराधेय इकाई माना जाता है;

(ङ) "कम्पनी" पद से कोई ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कम्पनी अथवा निगमित निकाय माना जाता है;

(च) "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है, इस पद में हर स्थिति में ये शामिल होंगे अचल सम्पत्ति के उप-साधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपकरण, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार जलयान, नौकाएं तथा विमान, यह सब अचल सम्पत्ति पद में सम्मिलित नहीं होंगे;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "राष्ट्रिक" पद का अर्थ है :

(i) भारत गणराज्य के संदर्भ में, भारत गणराज्य का कोई राष्ट्रिक और कोई भी विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्था जिसे अपनी यह हैसियत भारत गणराज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

(ii) जर्मन संघीय गणराज्य के संदर्भ में, जर्मन संघीय गणराज्य के मूल कानून के अनुच्छेद 116 के पैराग्राफ (1) की परिभाषा के अनुसार कोई जर्मन और कोई भी विधिक व्यक्ति भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत जर्मन संघीय गणराज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

(झ) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक ऐसे उद्यम द्वारा संचालित हो, जिसका प्रभावी प्रबन्ध स्थान किसी एक संविदाकारी राज्य में स्थित हो सिवाय उस स्थिति के, जलयान अथवा वायुयान दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

(ञ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है - जर्मन संघीय गणराज्य के मामले में, संघीय वित्त मंत्रालय तथा भारत के मामले में केन्द्रीय

सरकार का वित्त मंत्रालय "राजस्व विभाग" अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(ट) "वित्तीय वर्ष" पद से अभिप्रेत है :

- (i) भारतीय कर के मामले में, आयकर अधिनियम, 1961 में यथापरिभाषित पूर्ववर्ती वर्ष;
- (ii) जर्मन कर के मामले में, कैलेंडर वर्ष।

(ठ) "कर" पद का आशय संदर्भ के अनुसार जर्मन कर अथवा भारतीय कर से है परन्तु उसमें इन करों के संबंध में लगाया गया ब्याज अथवा अर्थ-दंड शामिल नहीं होगा।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के आधार पर वहां पर कर लगाया जा सकता है परन्तु इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसके द्वारा उस राज्य में केवल इसलिए कर देय हो क्योंकि आय का स्रोत अथवा कर योग्य सम्पत्ति उस राज्य में स्थित है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी:

(क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) हों ;

(ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता अथवा यदि उसे दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न को हल करेंगे।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध-स्थान स्थित है।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं:—

(क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा;

(ग) कोई कार्यालय;

(घ) कोई कारखाना;

(ङ) कोई कार्यशाला;

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुंआ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान, जिसमें खोज करने अथवा निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त कोई संस्थापन अथवा संरचना भी शामिल है;

(छ) कोई भाण्डागार अथवा बिक्री केन्द्र;

(ज) कोई फार्म, बागान अथवा कोई अन्य स्थान जहां कृषि, यानिकी, बागवानी अथवा सम्बद्ध कार्य-कलाप किए जाते हों; और

(झ) कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण-कार्य, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, जहां ऐसा भवन स्थल परियोजना अथवा कार्य-कलाप छः मास से अधिक की अवधि के लिए चलता रहता हो।

3. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना तथा उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करना तभी माना जाएगा यदि वह इस संबंध में सेवाएं अथवा सुविधाएं प्रदान करता है अथवा उस राज्य में खनिज तेलों को खोजने अथवा निष्कर्षण अथवा उपयोग में लाए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी किराये पर मुहैया करता है।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा:

(क) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग।

(ख) केवल भण्डारण प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनाथ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनाथ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना ;

(घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनाथ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;

(ङ) उद्यम के लिए केवल किसी अन्य पारिभाषिक अथवा सहायक स्वरूप के कार्यकलाप चलाने के प्रयोजनाथ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;

(च) उप-पैराग्राफ (क) से ड.) में उल्लिखित कार्यकलापों के मात्र संयोजन के लिए कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना, यशर्त कि उस संयोजन के परिणामतः कारोबार के निश्चित स्थान के समग्र कार्यकलाप प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति जो एक स्वतंत्र हैसियत वाले अधिकर्ता से भिन्न है जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता है, एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य की ओर से कार्य करता है तो उसका प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि उस व्यक्ति को :—

(क) उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आमतौर से उस राज्य में प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं की खरीद तक सीमित न हों ;

(ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं हो परन्तु वह प्रथमोक्त राज्य में आमतौर पर माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की निर्यात रूप से डिलीवरी करता हो ; अथवा

(ग) वह प्रथमोक्त राज्य में पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया उस उद्यम के लिए, अथवा उद्यम और अन्य नियंत्रणकारी अथवा नियंत्रित उद्यमों के लिए आर्डर प्राप्त करता हो और ऐसा उसी नियंत्रण के अन्तर्गत हो जिसके अन्तर्गत वह उद्यम हो ।

6. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में केवल इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले अधिकर्ता के माध्यम से कारोबार करता है, यशर्त कि ऐसे व्यक्ति अपना कारोबार सामान्य रूप से कर रहे हों और उद्यम के साथ उनके वारिष्ण्यिक और वित्तीय संबंधों के बारे में किन्हीं शर्तों पर सहमति न हुई हो अथवा ऐसी शर्तें न लगाई गई हों, जो दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच सामान्यतया सम्मत शर्तों से भिन्न हों ।

7. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है अथवा किसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार करती है (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) तो मात्र इस तथ्य से उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उते किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध, किसी उद्यम को अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद—7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा यदि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता । यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरीके से दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार करता है तो उस उद्यम के लाभ पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है किन्तु उसके केवल उतने अंश पर ही कर लगाया जा सकेगा जो कि उस स्थायी संस्थापन के कारण हो ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन, जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए कारोबार करता हो, वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभों को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जायेगा जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह वैसी ही या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में वैसी ही या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और पृथक् उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र कारोबार करता, जिसका कि यह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभ का निर्धारण करने में, उन व्यक्तियों को कटौतियों के रूप में ध्येय किया जायेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र तथा वे कटौतियों उस संविदाकारी राज्य जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो, के अन्तर्देशीय कानून के अनुसार की जाएंगी ।

4. जहाँ तक किसी संविदाकारी राज्य में तथा विशेष मामलों में किसी स्थायी संस्थापन के द्वारा अर्जित लाभ का पैराग्राफ 2 के अनुसार आंकलन असंभव हो या इससे अनुचित कठिनाईयां उत्पन्न हों, वहाँ पैराग्राफ 2 की कोई भी व्यवस्था उस लाभ को निश्चित करने में बाधक नहीं होगी यदि उस उद्यम के कुल लाभ का आंकलन और उस लाभ का प्रभाजन किसी अन्य उचित आधार पर किया गया हो, परन्तु, लाभ के प्रभाजन या आंकलन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी हो कि इससे निकलने वाले परिणाम इस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के अनुरूप हों ।

5. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी गई हैं ।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभ को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि इसके विरुद्ध कोई उचित तथा पर्याप्त कारण उपस्थित न हों ।

7. जहाँ लाभ में आय की वे मर्दे शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्तर्गत अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद—8**जलयानों तथा वायुयानों द्वारा परिवहन**

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों तथा वायुयानों के परिचालन से होने वाले लाभ पर केवल संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित हों।

2. यदि किसी जहाजगनी उद्यम का प्रभावी प्रबंध-स्थान, जलयान में हो, तो इसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिस देश में उसका घरेलू बन्दरगाह स्थित है, यदि कोई ऐसा स्वदेशी बन्दरगाह नहीं है, तो इसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसका निवासी उस जलयान का प्रचालक है।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से हुए लाभ के रूप में माना जाएगा तथा अनुच्छेद 11 के उपबंध के ऐसे ब्याज के मामलों में लागू नहीं होंगे।

4. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभ पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद—9**सम्बद्ध उद्यम**

जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) एक ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है;

और दोनों में से किसी के भी मामले में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के न होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त होता किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद—10**लाभांश**

1. एक संविदाकारी राज्य की किसी निवासी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में, उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लाभांश अदा करने वाली कंपनी जिसकी निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी

स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांश की सकल राशि का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस पैराग्राफ का प्रभाव कंपनी के उन लाभों के कर दायित्व पर नहीं पड़ेगा जिसमें से लाभांश लिया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “लाभांश” शब्द का अभिप्राय है :

(क) शेयरों पर लाभांश और शेयरों से आय और “जयोसेंस” शेयर्स अथवा “जयोसेंस” राइट्स, खनन शेयर, प्रवर्तक के शेयर अथवा अन्य राइट्स, जो लाभों में भागीदारी करने वाले ऋणदायक नहीं हैं।

(ख) अन्य आय जिस पर उस राज्य के, जिसकी वितरण करने वाली कंपनी एक निवासी है, कानूनों के अनुसार उसी प्रकार कर लगाया जाता है, जो शेयरों से प्राप्त आय पर लागू हो।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांश का हितभागी स्वामी तो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी, वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के लाभांशों की अदायगी की जाती है, वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो लागू होंगे।

5. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां दूसरा राज्य, कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा सिवाय इसके कि जो लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किया जाता हो अथवा जहां तक कि उस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, वहां उस दूसरे राज्य में कंपनी के अतिरिक्त लाभों पर, अतिरिक्त लाभ संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद—11**ब्याज**

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी :

(क) भारत गणराज्य में अर्जित होने वाले और जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार, डीयच्छ बुन्देस बैंक, क्रेडिटान्स्टाल्टफ्यूर आउफ्बाइ डीयच्छ इन्वेस्टीशन्स उंड एंड विकलुंग्सगेल्सशाफ्ट

(डी. ई. जी.) को दिया गया ब्याज और हेरमेस डेकुंग द्वारा दी गई गारन्टी वाले किसी ऋण के प्रतिफल में दिए गए ब्याज पर भारतीय कर में छूट होगी:

(ख) जर्मन संघीय गणराज्य में अर्जित होने वाले और भारत गणराज्य की सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक को दिये गये ब्याज पर जर्मन कर से छूट होगी।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रस्तुत “ब्याज” शब्द से अभिप्रेत है—प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्राप्य हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों। विलम्ब अदायगी के लिए जुर्मानों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।

5. पैराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबंध, यथा स्थिति लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज देने वाला संविदाकारी राज्य उसका प्रदेश, उस राज्य का कोई राजकीय उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो। किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से अधिक है, जो ऐसा विशेष संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमत हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम उल्लिखित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद — 12

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा। लेकिन यदि प्राप्तकता रायल्टियों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त रायल्टी शब्द से मार्हात्यक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी कॉपीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए जिनमें सिनेमा-फिल्में, टेलीविजन के संबंध में उपयोग में आने वाली फिल्मों अथवा वीडियो टेपें अथवा रेडियो प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल के लिए टेपें भी शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया औद्योगिक वाणिज्यिक उपकरणों के लिए औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस” पद में प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्श-दात्री सेवाओं के लिए, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, प्रतिफल के रूप में किसी रकम की अदायगियां अभिप्रेत हैं। लेकिन उसमें इस करार के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए अदायगियां शामिल नहीं हैं।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य, जिसमें रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उद्भूत होते हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है तथा जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा संविदा के संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा किए जाते हैं, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बन्धित है। ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।

6. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब रायल्टियां और फीस अदा करने वाला स्वयं वह कोई प्रदेश अथवा उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी

सेवाओं के लिए फीस स्थायी उस संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण प्रदत्त रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जितनी रकम के बारे में ऐसा संबंध न होने की स्थिति में अदा की होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम उल्लिखित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामलों में इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए अदायगियों का अतिरिक्त भाग प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा।

अनुच्छेद—13

पूँजीगत अभिलाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल-सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल-सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम के प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है।

4. किसी ऐसी कम्पनी के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. पैराग्राफ 1 से 4 तक में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न, किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

अनुच्छेद—14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उस राज्य में कराधेय होगी :

- (क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल

उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा, जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

- (ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके उठरने की अवधि अथवा अवधियां संगत वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 120 दिनों अथवा उससे अधिक हों, तो उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती हो।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दंत-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद—15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19 और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा यदि, नियोजन उस राज्य में किया गया है।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में, ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है; और

- (ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से चुकाया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और

- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान, जो नियोजन का दूसरे राज्य में हो, द्वारा वहन नहीं किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में परिचालित जलयान अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसका कि जलयान अथवा वायुयान का संचालन करने वाला उद्यम निवासी है।

अनुच्छेद—16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हों, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद—17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा

किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. तथापि, ऐसी आय पर पैराग्राफ 1 में उल्लिखित राज्य में कर नहीं लगेगा यदि उक्त कार्यकलाप दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा उस राज्य के दौरे के दौरान किए जाते हैं और जहां ऐसे दौरे उस दूसरे राज्य, उसके किसी प्रदेश, किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः समर्थित होते हैं अथवा किसी ऐसे संगठन द्वारा समर्थित होते हैं जो उस दूसरे राज्य में एक धर्मार्थ संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अनुच्छेद—18

गैर-सरकारी पेंशन

अनुच्छेद 19 के उपबंधों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को पिछली सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद—19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य, उसके किसी प्रदेश, किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके प्रदेश, उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गयी पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा।
- (ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, जो :
 - (i) उस राज्य का राष्ट्रिक है ; अथवा
 - (ii) मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।
2. (क) किसी संविदाकारी राज्य, उसके किसी प्रदेश, किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य, उसके प्रदेश, उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा।
- (ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि व्यक्ति उस अन्य राज्य का निवासी और एक राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी प्रदेश, किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गयी सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।

4. इसी प्रकार, पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य, उसके किसी प्रदेश, किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के विकास सहायक कार्यक्रम के अंतर्गत उस राज्य, प्रदेश, राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनन्य रूप से प्रदान की गई निधि में से उस दूसरे राज्य की सहमति से किसी विशेषज्ञ अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के लिए समर्थित स्वयं-सेवक को अदा किए गए पारिश्रमिक के संबंध में भी लागू होंगे।

अनुच्छेद—20

अध्यापक, विद्यार्थी और प्रशिक्षार्थी

1. कोई व्यक्ति जो उस राज्य अथवा उस राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, संग्रहालय अथवा अन्य सांस्कृतिक संस्था के निमंत्रण पर अथवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के किसी सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी संस्था में अध्यापन, व्याख्यापन अथवा अनुसंधान करने के प्रयोजन के लिए मात्र दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए किसी संविदाकारी राज्य में जाता है और जो उस दौरे से तुरन्त पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, उसके आगमन की तारीख से प्रथम वर्ष की अवधि के दौरान ऐसे कार्यकलाप के लिए उसके पारिश्रमिक पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट दी जाएगी और अगले वर्ष में केवल उस राज्य के बाहर से उसे प्राप्त हुए पारिश्रमिक के संबंध में ही छूट दी जाएगी।

2. जो व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य में अनन्यतः रहता है:—

- (क) उस संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय अथवा विद्यालय में विद्यार्थी के रूप में;
 - (ख) व्यावसायिक प्रशिक्षु के रूप में (इसमें जर्मन संघीय गणराज्य के मामले में "वोजोन्टेयर" अथवा कोई "प्राक्टिकान्ट" भी शामिल हैं);
 - (ग) अध्ययन अथवा अनुसंधान के मूलतः प्रयोजन के लिए किसी धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक अथवा शैक्षणिक संगठन के अनुदान, भत्ता अथवा पुरस्कार पाने वाले के रूप में; अथवा
 - (घ) उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा प्रवृत्त किसी तकनीकी सहकारिता कार्यक्रम के सदस्य के रूप में;
- और जो उस राज्य में जाने से तुरन्त पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा निवासी था, उसे प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी:
- (i) उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए विदेश से प्रेषित रकमों के संबंध में ; और
 - (ii) उस दूसरे राज्य में नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में जो किसी वित्तीय वर्ष में डी एम 7,200 (सात हजार दो सौ) से अनधिक रकम नहीं हो अथवा भारतीय मुद्रा में इसके समकक्ष हो, यथा स्थिति बशर्त कि ऐसा नियोजन सीधे उसके

अध्ययन से संबंधित है अथवा उसके भरण-पोषण के प्रयोजन के लिए किया गया है।

अनुच्छेद—21

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहाँ-कहाँ वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है। केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध यथा स्थिति लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्रोतों से लाटरियों, वर्ग पहेलियों, घुड़दौड़ सहित दूसरी दौड़ों, ताश और किसी प्रकार के अन्य खेलों अथवा जुआ अथवा किसी भी स्वरूप की शर्तों के संबंध में आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद—22

पूंजी

1. किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा स्वामित्वाधीन और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति वाली पूंजी पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का हिस्सा बनने वाली चल संपत्ति के रूप में निरूपित पूंजी जो किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में लगाई गई हो, अथवा ऐसी चल संपत्ति जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की ऐसी अचल संपत्ति से संबंधित हो जो दूसरे संविदाकारी राज्य में है और जिसका प्रयोग उसके स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के लिए किया जाता है, उस पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिचालित, जलयानों और वायुयानों तथा ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल संपत्ति को निरूपित करने वाली पूंजी पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है।

4. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूंजी के अन्य सभी हिस्सों पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा।

अनुच्छेद—23

दोहरे कराधान से राहत

1. जर्मन संघीय गणराज्य के किसी निवासी के मामले में कर निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाएगा:—

(क) उप-पैराग्राफ (ख) के अंतर्गत जब तक कि विदेश कर क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाती, भारत गणराज्य में उद्भूत होने वाली आय की कोई मद और भारत गणराज्य में स्थित

पूंजी की किसी मद को जर्मन कर से छूट दी जाएगी, जिस पर इस करार के अनुसार भारत में कर लग सकेगा। तथापि, जर्मन संघीय गणराज्य इस प्रकार की आय और पूंजी की मदों पर कर की दर के निर्धारण करने का अधिकार बनाए रखता है। लाभांशों के मामले में छूट केवल ऐसे लाभांशों पर ही लागू होगी जैसी कि किसी कम्पनी को भारत गणराज्य के किसी निवासी के नाते किसी कम्पनी द्वारा जर्मन संघीय गणराज्य के निवासी होने के नाते (जिसमें भागीदारी शामिल नहीं) उस पूंजी का कम से कम 10 प्रतिशत अदा करती है जो जर्मन कम्पनी द्वारा प्रत्यक्षतः धारित होती है। ऐसे शेयरों पर पूंजी पर लगाए गए कर पर छूट दी जाएगी जिसके लाभांश पर कर नहीं लगाया जाता अथवा यदि कर दिया जाता है तो पूर्वोक्त वाक्य के अनुसार उसमें छूट दी जायेगी।

(ख) विदेश कर के लिए क्रेडिट के बारे में जर्मन कर कानून के उपबंधों के अधधीन भारत गणराज्य में उद्भूत होने वाली आय और उसमें स्थित पूंजी की निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में देय जर्मन कर के प्रति क्रेडिट के रूप में अनुमति दी जाएगी और भारत के कानूनों के अंतर्गत और इस करार के अनुसार निम्नलिखित पर भारतीय कर अदा किया गया है :

(i) लाभांश, जिन पर उप-पैराग्राफ (क) में विचार नहीं किया गया है;

(ii) ब्याज;

(iii) रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस;

(iv) अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4 के अर्थों में आय;

(v) निदेशकों की फीस;

(vi) कलाकारों और खिलाड़ियों की आय;

(ग) उप-पैराग्राफ (ख) के वर्ण (ii) में उल्लिखित क्रेडिट के प्रयोजन के लिए भारतीय कर ब्याज की सकल रकम का 10 प्रतिशत माना जाएगा, यदि वास्तव में अदा किए गए कर की रकम पर ध्यान दिए बिना भारतीय कर को घरेलू कानून के अनुसार किसी न्यूनतर दर तक घटाया जाता है अथवा पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है;

(घ) उप-पैराग्राफ (ग) के उपबंध प्रथम 12 वर्षों के लिए लागू होंगे जिसके लिए यह करार प्रभावी है;

(ङ) उप-पैराग्राफ (क) के उपबंधों के रहते हुए भी, अनुच्छेद 7 और 10 में विचार की गई आय की मदों और किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों के साथ ही साथ ऐसी आय की अन्तर्निहित पूंजी की मदों को जर्मन कर से तभी छूट दी जाएगी यदि जर्मन संघीय गणराज्य का निवासी यह सिद्ध कर सकता हो कि स्थायी संस्थापन अथवा कम्पनी की प्राप्तिमात्र मात्र अथवा प्रायः मात्र सक्रिय संचालनों से प्राप्त होती हैं।

अनुच्छेद 10 में विचार की गई आय की मदों और ऐसी आय की

अंतर्निहित पूंजी की मदों के बारे में भी छूट लागू होगी भले ही लाभांश भारतीय नागरिक होने के नाते उन दूसरी कम्पनियों की सम्पत्तियों से प्राप्त होते हों जो सक्रिय संचालन करती हैं और जिसमें वह कम्पनी, जिसमें अंत में वितरण किया है, 25 प्रतिशत से अधिक की धारक है। सक्रिय संचालन निम्नलिखित हैं :

भारत गणराज्य के भीतर माल अथवा पण्य-वस्तुओं का उत्पादन अथवा विक्रय, तकनीकी सलाह देना अथवा इंजीनियरिंग संबंधी सेवाएं देना अथवा बैंकिंग कार्य अथवा बोमा कारोबार करना।

यदि यह प्रमाणित नहीं होता है, तो केवल उप-पैराग्राफ (ख) के अनुसार क्रेडिट प्रक्रिया लागू होगी।

2. भारत गणराज्य के किसी निवासी के मामले में कर निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाएगा :

जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूंजी रखता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार, जर्मन संघीय गणराज्य में कर लगेगा, वहां भारत चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती के द्वारा उस निवासी की ऐसी आय पर जर्मन संघीय गणराज्य में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर और उस निवासी की ऐसी पूंजी पर जर्मन संघीय गणराज्य में अदा की गई पूंजी पर कर की रकम के बराबर कर से कटौती के रूप में अनुमति देगा। तथापि, दोनों ही मामलों में, ऐसी कटौती की रकम आयकर अथवा पूंजी कर (कटौती दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित) यथा-स्थिति के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो कि आय अथवा पूंजी के कारण हो, जिस पर जर्मन संघीय गणराज्य में कर लगाया जा सकता है।

3. दोनों संविदाकारी राज्यों में लागू कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय और पूंजी के कराधान को शामिल करने के संबंध में जारी रहेंगे सिवाय उसके, जहां इसके प्रतिकूल सुस्पष्ट उपबंध इस करार में किए गए हैं।

अनुच्छेद—24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों को वैसी ही परिस्थितियों में और वैसे ही उपबंधों के अधीन लगाए जाने वाले कराधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हों। यह उपबंध अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन को, उस दूसरे राज्य में, ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों में समरूप कार्यकलाप को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य को किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर, कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है, जोकि उस दर से अपेक्षाकृत अधिक है, जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की उसी प्रकार की कम्पनी के लाभों पर लगाई जाती है, और न ही

अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल हो। इसके अलावा इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकारी है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को कराधान के प्रयोजनों के लिए वही व्यक्तिगत छूटें, राहतें और छटौतियां प्रदान करें जो कि वह केवल अपने निवासियों को प्रदान करता है।

3. ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पर अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टियां और अन्य वितरण, ऐसे उद्यम के कर लगाने योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती पाने योग्य होंगे, जैसे कि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के निवासी को अदा किए गए थे। इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दिए गए कोई भी ऋण ऐसे उद्यम की कर लगाने योग्य पूंजी के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती पाने योग्य होंगे, जैसे कि प्रथमोल्लिखित राज्य के निवासी को अनुबंधित किए गए थे।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर वैसी ही शर्तों के अधीन लागू है अथवा हो सकती है।

अनुच्छेद - 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया जा रहा है अथवा लगाया जाएगा जो कि इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है, तो वह अपना मामला उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण उस पर कर लग सकता है जो इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किये गये किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा, चाहे संविदाकारी राज्यों के आन्तरिक कानूनों में कोई समय-सीमा क्यों न हो।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक समझौते से हल करने का प्रयास करेंगे। वे, उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनकी उस करार में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी करों में छूट अथवा कटौती के संबंध में इस करार के उपबंधों को लागू करने के लिए पारस्परिक सहमति द्वारा निर्धारित तरीके के निर्णय ले सकते हैं।

5. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अर्थ में किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

अनुच्छेद-26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है। किसी भी संविदाकारी राज्य के द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार कि उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना समझी जाती है और इस सूचना को केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से सम्बद्ध हों, जो करार के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही कर सकेंगे। वे, सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:—

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गुप्त अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद-27

राजनयिक और कांसुली विशेषाधिकार

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशन के सदस्यों अथवा कांसुली अधिकारियों अथवा किसी अन्तराष्ट्रीय संगठन के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद-28

प्रवर्तन

1. संविदाकारी राज्यों की सरकारें एक-दूसरे को इस आशय की अधिसूचना भेजेंगी कि इस करार को लागू करने के लिए कानूनी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं।

2. यह करार पैराग्राफ 1 में संदर्भित अधिसूचना के बाद में जारी किए गए पत्रों की तारीख के पश्चात लागू होगा और इस प्रकार प्रभावी होगा :

(क) भारत गणराज्य में :

(i) जिस कैलेंडर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिवस को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;

(ii) जिस कैलेंडर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिवस को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को धारित पूंजी के संबंध में;

(ख) जर्मन संघीय गणराज्य में :

(i) लाभांशों, ब्यज, रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर स्रोत पर लगाए गए करों के मामले में, जिस कैलेंडर वर्ष में यह करार लागू होता है, उसके बाद वाले वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिवस को अथवा बाद में अदा की गई राशियों के संबंध में;

(ii) अन्य करों के मामले में, जिस कैलेंडर वर्ष में यह करार लागू होता है, उसके बाद वाले वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिवस को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाली अवधियों के लिए लगाए गए करों के संबंध में।

3. इस करार के लागू हो जाने पर, आय तथा पूंजी पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए जर्मन संघीय गणराज्य तथा भारत सरकार के बीच दिनांक 18 मार्च, 1959 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार तथा आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए वह प्रोटोकोल जिसके द्वारा जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार का संशोधन किया गया था और जिस पर टिप्पणियों के आदान-प्रदान के सहित, 28 जून, 1984 को हस्ताक्षर किये गए हैं, रद्द हो जाएंगे और उनकी मान्यता का उस दिन से अन्त हो जाएगा जिस दिन से यह समझौता लागू होगा।

अनुच्छेद-29

समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा परन्तु दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष में जून की तीस तारीख को अथवा उससे पहले दूसरे संविदाकारी राज्य को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप से इसके समापन की सूचना दे सकता है। ऐसी स्थिति में, यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) भारत गणराज्य में :

(i) जिस कैलेंडर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिवस को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;

(ii) जिस कैलेंडर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिवस को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को धारित पूंजी के संबंध में;

(ख) जर्मन संघीय गणराज्य में :

(i) जिस कैलेंडर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिवस को अथवा उसके पश्चात् अदा की गई राशियों के संबंध में लाभांशों, ब्याज, रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर स्रोत पर लगने वाले करों के संबंध में;

(ii) अन्य करों के संबंध में जिस कैलेंडर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिवस को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाली अवधियों के लिए लगाए गए करों के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

बौन में वर्ष एक हजार नौ सौ पंचानबे के जून माह के उन्नीसवें दिन हिन्दी, जर्मन और अंग्रेजी भाषा में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और तीनों मूल पाठ प्रमाणिक हैं।

हिन्दी तथा जर्मन पाठ में अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रमाणिक माना जाएगा।

भारत गणराज्य की ओर से	जर्मन संघीय गणराज्य की ओर से
ह./	ह. अपठनीय
मनमोहन सिंह	[अधिसूचना सं०:10235 दिनांक 29-11-96/ फा० सं० 500/47/90-वि० क० प० भाग] एन. पी. माहनी, संयुक्त सचिव

प्रोटोकोल

भारत गणराज्य

और

जर्मन संघीय गणराज्य

आय और पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए निर्मलखित उपबंध जो कि उक्त करार के अनिवार्य अंग बनेंगे, के लिए दो राज्यों के बीच दिनांक 19-6-1995 को करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए हैं।

1. अनुच्छेद 7 के संबंध में :

(क) किसी भवन-स्थल अथवा निर्माण-कार्य, संयोजन अथवा संस्थापन परियोजना के लाभ का निर्धारण करने के लिए यह उस संविदाकारी राज्य के स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाएंगे जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है और केवल स्थायी संस्थापन के कार्यकलाप से होने वाले लाभों को ही उनमें शामिल किया जाएगा। यदि इन कार्यकलापों के संबंध में अथवा इनसे उत्पन्न स्वतंत्र रूप से प्रधान कार्यालय अथवा उद्यम के किसी अन्य स्थायी संस्थापन से (जो उस संविदाकारी राज्य से बाहर स्थित हो) अथवा किसी तीसरे व्यक्ति (जो उस संविदाकारी राज्य से बाहर स्थित हो) से मशीनरी अथवा उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं तो यह लाभ भवन-स्थल अथवा निर्माण-कार्य, संयोजन अथवा संस्थापन परियोजना, ऐसे उपलब्ध कराए जाने के मूल्य के कारण हुए नहीं माने जाएंगे।

(ख) किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा आयोजना, परियोजना, निर्माण-कार्य अथवा अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों द्वारा प्राप्त की गई आय और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन के संबंध में उस राज्य में की गयी तकनीकी सेवाओं से होने वाली आय, स्थायी संस्थापन से होने वाली आय नहीं मानी जाएगी।

(ग) अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के संबंध में, उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसी अथवा समान प्रकार के माल पण्य वस्तुओं की बिक्री में जैसे कि पहले बेची गयी हैं अथवा उसी अथवा समान प्रकार के अन्य व्यावसायिक कार्यकलाप जैसे पहले किए गए क्रियाकलापों से प्राप्त लाभ, उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाएंगे यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि :

(i) यह लेन-देन उस संविदाकारी राज्य में कराधान से बचने के लिए किया गया है जहां स्थायी संस्थापन स्थित है; और

(ii) वह स्थायी संस्थापन इस लेन-देन में किसी भी प्रकार से शामिल था।

(घ) यह समझा जाता है कि प्रधान कार्यालय के व्ययों के संबंध में कटौतियों, जैसा कि अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 में संदर्भित है, किसी भी स्थिति में उन कटौतियों से कम नहीं होंगी जो इस करार के लागू होने की तारीख से भागतीय अद्यतन अधिनियम के अंतर्गत अनुमत्य हैं।

(ङ) उद्यम के प्रधान कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य कार्यालय के स्थायी संस्थापन को निम्नलिखित रूप से अदा की गयी अथवा उसके द्वारा प्रभारित (वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा) राशियों के संबंध में कोई कटौती अनुमत्य नहीं होगी।

(i) पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के इस्तेमाल के एवज में रायल्टियां, फीसें अथवा ऐसी ही अन्य अदायगियां ;

(ii) निष्पादित की गयी विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध के लिए कमीशन ;

(iii) बैंकिंग संस्था के मामले को छोड़कर स्थायी संस्थापन को उधार दी गयी राशि पर ब्याज।

2. अनुच्छेद 8 के संदर्भ में :

अनुच्छेद 8 के प्रयोजनों के लिए जलयानों के परिचालन से प्राप्त आय में अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के संबंध में आधानों (जिनमें आधानों के परिवहन के लिए संबंधित उपकरण और दस्तावेज शामिल हैं) के इस्तेमाल, रख-रखाव, उनको किराये पर देने से प्राप्त की गयी आय भी शामिल है।

3. अनुच्छेद 10 के संदर्भ में :

जर्मन संघीय गणराज्य में कराधान के प्रयोजन के लिए लाभांश शब्द में एक निष्क्रिय साझेदार (शिटलर गेजेल्शाफ्टर) द्वारा उसकी साझेदारी से प्राप्त आय और किसी निवेश निधि अथवा निवेश न्यास के प्रमाण-पत्रों पर दी गयी वितरणों की आय भी शामिल है। इस प्रयोजन के लिए भारत में ऐसी ही आय को इसी रूप में माना जाएगा।

4. अनुच्छेद 10 और 11 के संदर्भ में :

इन अनुच्छेदों के उपबंधों के होते हुए भी लाभांशों और ब्याज पर उस राज्य में जिसमें वे उद्भूत होते हैं, उस राज्य में और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है :

(क) यदि वे अधिकारों से अथवा ऐसे ऋण दावों से प्राप्त होते हैं जिनमें लाभों में भागीदारी का हक प्राप्त है (इसमें किसी निष्क्रिय साझेदार द्वारा प्राप्त ऐसी आय भी शामिल है, जो जर्मन संघीय गणराज्य के कर-कानूनों के अर्थ के अंतर्गत "पार्टिआरिसिच दारलेहन" और "गेविन ओबलिगेटि ओनिन" से उसकी इस प्रकार की भागीदारी से प्राप्त हुई हो); और

(ख) इस शर्त के अधीन कि ऐसी आय के देन दार के लाभों का निर्धारण करने में उनकी कटौती की जाये।

5. अनुच्छेद 13 के संदर्भ में :

जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार की ओर से पुष्टिकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि डॉयत्शे इन्वेस्टीत्सियोन्स—उंड एन्टविकलुंग्स—गेलेल्शाफ्ट डी. ई. जी. जर्मन संघीय गणराज्य के पूर्णतः स्वामित्व में है और जर्मनी में इसे आयकर से छूट प्राप्त है, इस पर सहमति हो गई है कि भारतीय कम्पनियों में शेयरों के हस्तांतरण के कारण डी. ई. जी. को प्राप्त होने वाले लम्बी अवधि के पूँजीगत अभिलाभों पर भारत में कराधान से छूट प्राप्त होगी।

6. अनुच्छेद 23 के संदर्भ में :

(क) पैराग्राफ 1 उप-पैराग्राफ (क) में उपलब्ध कराई गई छूट, इस बात को ध्यान में रखे बिना प्रदान की जाती है कि संबंधित आय अथवा पूँजी पर भारत गणराज्य में प्रभावी ढंग से कर लगाया जाता है या नहीं।

(ख) जहां कोई कम्पनी, जर्मन संघीय गणराज्य की निवासी होने के नाते भारत गणराज्य के भीतर के स्रोतों से प्राप्त की गई आय का वितरण करती है, वहां जर्मन कर कानून के उपबंधों के अनुसार ऐसे वितरणों पर पूरक निगमित कर लगाने पर पैराग्राफ 1 प्रतिबंधित नहीं होगा।

(ग) जर्मन संघीय गणराज्य अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 1(ख) में उपलब्ध कराए गए कर क्रेडिट द्वारा दोहरे कराधान का परिहार करेगा न कि अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ (क) के अंतर्गत दी गई कर छूट द्वारा।

(कक) यदि संविदाकारी राज्यों में आय को अनुच्छेद 9 के अंतर्गत के अलावा करार के भिन्न-भिन्न उपबंधों के अंतर्गत रखा जाता है अथवा विभिन्न व्यक्तियों के नाम लगाया जाता है और इस झगड़े को अनुच्छेद 25 में विहित कार्यविधि के अनुसार निपटाया नहीं जा सकता और

(i) यदि ऐसा होने के परिणाम-स्वरूप अथवा स्थान-निर्धारण के कारण संगत आय पर दोहरा कर लगाया जाएगा; अथवा

(ii) यदि ऐसा होने के परिणाम-स्वरूप अथवा स्थान-निर्धारण के कारण संगत आय पर भारत में कर नहीं लगाया जाता अथवा अनुपयुक्त रूप से कम कर लगाया जाता है और इस पैराग्राफ के प्रवर्तन से अन्यथा जर्मन संघीय गणराज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, अथवा

(खख) यदि जर्मन संघीय गणराज्य ने यथोचित परामर्श के पश्चात् और अपने अन्तरराष्ट्रीय कानून की सीमाओं के अंतर्गत राजनयिक माध्यमों से भारत गणराज्य को आय को अन्य मदों के बारे में अधिसूचित किया है जिन पर यह पैराग्राफ लागू है जिससे कि दोनों संविदाकारी राज्यों में आय पर कराधान की छूट को रोका जा सके अथवा करार के अनुपयुक्त हस्तमाल के अन्य तरीकों को रोका जा सके।

उप-पैराग्राफ (ख) के अंतर्गत की अधिसूचना के मामले में भारत गणराज्य राजनयिक माध्यमों से अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए करार के अंतर्गत जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा निर्धारित कर सकता है। इस पैराग्राफ के तहत जारी की गई अधिसूचना उस कैलेंडर वर्ष के बाद वाले वर्ष के प्रथम दिवस को प्रभावी होगी, जिस वर्ष में यह भेजी गई थी और इसे प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचित करने वाले राज्य के द्वारा कानूनी पूर्व अपेक्षाएं देशीय कानून के अंतर्गत पूरी कर ली गई हों।

7. अनुच्छेद 26 के संदर्भ में :

(क) यह भी समझा जाता है कि करार के संबंध में "सूचना" पद में दस्तावेज शामिल होंगे। इसके अलावा यह भी समझा जाता है कि जर्मन कर कानून में राजस्व संहिता अवगायेन ऑर्डनिंग के अनुच्छेद 117 के पैराग्राफ 3 के अर्थ में अनुरोध पर सूचना भेजने का प्रावधान है—और इस अनुच्छेद के होते हुए भी इन उपबंधों के अंतर्गत भारत में संक्षम प्राधिकारी को सूचना प्रस्तुत करना संभव होगा।

(ख) यदि इस अनुच्छेद के तहत व्यक्तिगत आंकड़ों का आदान-प्रदान किया जाता है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त उपबंध लागू होंगे, बशर्ते कि प्रत्येक संविदाकारी राज्य के देशीय कानून को स्वीकार करते हों :

- (i) आंकड़े भेजने वाले संविदाकारी राज्य, भेजे गए आंकड़ों की परिशुद्धता के लिए जिम्मेवार होंगे। यदि यह पता चलता है कि अशुद्ध आंकड़े अथवा वे आंकड़े सप्लाई किए गए हैं, जो सप्लाई नहीं किए जाने चाहिए थे तो प्राप्तकर्ता राज्य को इस आशय से अविलम्ब अधिसूचित किया जाएगा। उस राज्य के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह उन आंकड़ों को ठीक करे या उनको नष्ट कर दे ;
- (ii) संविदाकारी राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे व्यक्तिगत आंकड़ों को भेजने अथवा प्राप्त करने के सरकारी रिकार्ड संभाल कर रखें ;
- (iii) संविदाकारी राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे भेजे गए व्यक्तिगत आंकड़ों को अनधिकृत पहुँच, उनमें अनधिकृत परिवर्तन और उनकी अनधिकृत घोषणा से सुरक्षित रखें ;
- (iv) आवेदन करने पर संबंधित व्यक्ति को संग्रह की गई सूचना और उसके इस्तेमाल के बारे में सूचित किया जाएगा। यदि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हित की तुलना में सार्वजनिक हित में इस सूचना को रोके रखना अधिक महत्वपूर्ण हो, तो वह सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्य सभी मामलों में जिस व्यक्ति के बारे में आंकड़े संग्रह किए जाते हैं उसके द्वारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार उस संविदाकारी राज्यों के देशीय कानून द्वारा अधिशासित होगा, जिसमें सूचना के लिए आवेदन किया जाता है।

बीन में वर्ष एक हजार नौ सौ पंचानबे के जून माह के उन्नीसवें दिन हिन्दी, जर्मन और अंग्रेजी भाषा में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और तीनों मूल पाठ प्रमाणिक हैं।

हिन्दी तथा जर्मन पाठ में अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रमाणिक माना जाएगा।

भारत गणराज्य की ओर से जर्मन संघीय गणराज्य की ओर से
मन मोहन सिंह ह/ अपठनीय

[अधिसूचना सं. : 10235 दिनांक 29/11/96/

फा. सं. 500/47/90-वि. क. प्रभाग]

एन. पी. साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 1996

INCOME-TAX

S.O. 836(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Federal Republic of Germany for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital has been concluded;

And Whereas the aforesaid Agreement was brought into force on the 26th day of October, 1996 after the completion by both the Contracting States to each other of the procedure required under their laws in accordance with article 28 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

Annexure
Agreement
between the Republic of India
and the Federal Republic of Germany
for the Avoidance of Double Taxation
with respect to Taxes on Income and Capital

Whereas the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of India desire to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital and for promoting their mutual economic relations;

Now, therefore, it is hereby agreed as follows:

Article 1

Personal Scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes Covered

(1) This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State, of a land or a political subdivision or local authority thereof, irrespective of the procedure in which they are levied.

(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, and the payroll tax.

(3) The existing taxes to which this Agreement shall apply are in particular:

- (a) in the Federal Republic of Germany;
 - the Einkommensteuer (income tax),
 - the Körperschaftsteuer (corporation tax),
 - the Vermögensteuer (capital tax), and
 - the Gewerbesteuer (trade tax)
 (hereinafter referred to as "German Tax");

- (b) in the Republic of India;
 - the income tax including any surcharge tax thereon (Einkommensteuer, einschl. darauf entfallender Zusatzsteuern), and the wealth tax (Vermögensteuer)
 (hereinafter referred to as "Indian tax")

(4) This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the contracting States shall notify each other of charges of importance which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

General Definitions

(1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Federal Republic of Germany" means the area in which the tax law of the Federal Republic of Germany is in force including the area of the sea-bed, its sub-soil and the superjacent watercolumn adjacent to the territorial sea, insofar as the Federal Republic of Germany exercises their sovereign rights and jurisdiction in conformity with international law and its national legislation;
- (b) the term "Republic of India" means the territory of the Republic of India and includes the territorial sea and airspace above it. For the purposes of this Agreement the term shall also cover any other maritime zone in which the Republic of India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law in particular as laid down in the UN Convention of the law of the Sea;
- (c) the term "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Federal Republic of Germany or the Republic of India as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, a com-

pany and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective contracting States.

- (f) the term "immovable property" has the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property;

- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

- (h) the term "national" means:

- (i) in respect of the Federal Republic of Germany any German within the meaning of Article 116, paragraph (1), of the Basic Law for the Federal Republic of Germany and any legal person, partnership and association deriving its status as such from the law in force in the Federal Republic of Germany;

- (ii) in respect of the Republic of India any national of the Republic of India and any legal person, partnership and association deriving its status as such from the law in force in the Republic of India;

- (i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

- (j) the term "competent authority" means in the case of the Federal Republic of Germany the Federal Ministry of Finance and in the case of the Republic of India the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or its authorised representative;

(k) the term “fiscal year” means:

(i) in relation to Indian tax, the previous year as defined in the Income Tax Act, 1961;

(ii) in relation to German tax, the calendar year.

(l) the term “tax” means German tax or Indian tax as the context requires but shall not include interest or penalty imposed in relation to such taxes.

(2) As regards the application of this Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which this Agreement applies.

Article 4 Resident

(1) For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

Permanent Establishment

(1) For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term “permanent establishment” includes especially.

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources, including an installation or structure used for the exploration or exploitation;

(g) a warehouse or sales outlet;

(h) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on; and

(i) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities continue for a period exceeding six months.

(3) An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with, or supplies plant and machinery on hire used for or to be used in the prospecting for, or extraction or exploitation of mineral oils in that State.

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise,

any other activity of a preparatory or auxiliary character;

- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies—is acting in a contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, if this person

- (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;
- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- (c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise.

(6) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business and in their commercial and financial relations to the enterprise no conditions are agreed or imposed which differ from those usually agreed between independent persons.

(7) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from Immovable Property

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

(3) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

Business Profits

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, and according to the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

(4) Insofar as in a Contracting State and in exceptional cases the determination of the profits to be attributed to a permanent establishment in accordance with paragraph 2 is impossible or gives rise to unreasonable difficulties, nothing in paragraph 2 shall preclude the determination of the profits to be attributed to a permanent establishment by means of either apportioning the total profits of the enterprise to that permanent establishment or estimating on any other reasonable basis; the method of apportionment or estimation adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and Air Transport

(1) Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

(2) If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

(3) For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

(4) The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

Associated Enterprises

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this Article means

- (a) dividends on shares including income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, and
- (b) other income which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is resident.

(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, not subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

- (1) Interest arising in a Contracting State and paid to

a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2.

(a) interest arising in the Federal Republic of Germany and paid to the Government of the Republic of India, the Reserve Bank of India, the Industrial Finance Corporation of India, the Industrial Development Bank of India, the Export-Import Bank of India, National Housing Bank and Small Industries Development Bank of India shall be exempt from German tax;

(b) interest arising in the Republic of India and paid to the Government of the Federal Republic of Germany, the Deutsche Bundesbank, the Kreditanstalt für Wiederaufbau or the deutsche investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) and interest paid in consideration of a loan guaranteed by HERMES-Deckung shall be exempt from Indian tax.

(4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a Land, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is born by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent estab-

lishment or fixed base is situated.

(7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

Royalties and Fees for Technical Services

(1) Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or the fees for technical services.

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(4) The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount in consideration for the services of managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services by technical or other personnel, but does not include payments for services mentioned in Article 15 of this Agreement.

(5) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as

the case may be, shall apply.

(6) Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a Land or a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other Person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

Capital Gains

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (Alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

(3) Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

(4) Gains from the alienation of shares in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

(5) Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 to 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Independent Personal Services

(1) Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities, in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 120 days in the relevant fiscal year; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

(2) The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

Dependent Personal Services

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable in the other Contracting State only if the employment is exercised there.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State of which the enterprise operating the ship or aircraft is a resident.

Article 16

Directors' Fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and Sportspersons

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

(3) However, such income shall not be taxed in the State mentioned in paragraph 1 if the said activities are exercised during a visit to that State by a resident of the other Contracting State and where such visit is financed directly or indirectly by that other State, a Land, a political subdivision or a local authority thereof or by an organisation which in that other State is recognised as a charitable organisation.

Article 18

Non-government Pensions

Subject to the provisions of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

Government Service

(1) (a) Remuneration other than a pension, paid by a Contracting State, a Land, a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State, Land, subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State, if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

(2) (a) Any pension paid by a Contracting State, a Land, a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State, Land, subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of and a national of that other State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 8 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, a Land, a political subdivision or a local authority thereof.

(4) The provisions of paragraph 1 shall likewise apply in respect of remuneration paid, under a development assistance programme of a Contracting State, a Land, a political subdivision or a local authority thereof, out of funds exclusively supplied by that State, Land, political subdivision or local authority, to a specialist or volunteer seconded to the other Contracting State with the consent of that other State.

Article 20

Teachers, Students and Trainees

(1) An individual who visits a Contracting State at the invitation of that State or of a university, college, school, museum or other cultural institution of that state or under an official programme of cultural exchange for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching, giving lectures or carrying out research at such institution and who is, or was immediately before that visit, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned state on his remuneration for such activity during the period of the first year from the date of his arrival and in the next year the exemption will be only in respect of remuneration derived by him from outside that state.

(2) An individual who is present in a Contracting State solely

- (a) as a student at a university, college or school in that Contracting State.
- (b) as a business apprentice (including in the case of the Federal Republic of Germany a "Volontar" or a "Praktikant").
- (c) as the recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study or research from a religious, charitable, scientific or educational organisation, or.

(d) as a member of a technical cooperation programme entered into by the Government of that Contracting State, and who is, or was immediately before visiting that State, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the firstmentioned Contracting state in respect of

- (i) remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training and
- (ii) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding DM 7,200 (seven thousand two hundred Deutsche Mark) or its equivalent in Indian currency during any fiscal year, as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

Article 21

Other Income

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt within the foregoing articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting state through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if a resident of a Contracting state derives income from sources within the other Contracting state in the form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State.

Article 22

Capital

(1) Capital represented by immovable property, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting state, may be taxed in that other state.

(2) Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting state or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose

of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

(3) Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

(4) All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 23

Relief from Double Taxation

(1) Tax shall be determined in the case of a resident of the Federal Republic of Germany as follows:

- (a) Unless foreign tax credit is to be allowed under subparagraph (b), there shall be exempted from German tax any item of income arising in the Republic of India and any item of capital situated within the Republic of India, which, according to this Agreement, may be taxed in the Republic of India. The Federal Republic of Germany, however, retains the right to take into account in the determination of its rate of tax the items of income and capital so exempted.

In the case of dividends exemption shall apply only to such dividends as are paid to a company (not including partnerships) being a resident of the Federal Republic of Germany by a company being a resident of the Republic of India at least 10 per cent of the capital of which is owned directly by the German company.

There shall be exempted from taxes on capital any shareholding the dividends of which are exempted or, if paid, would be exempted, according to the immediately foregoing sentence.

- (b) Subject to the provisions of German tax law regarding credit for foreign tax, there shall be allowed as a credit against German tax payable in respect of the following items of income arising in the Republic of India and the items of capital situated there the Indian tax paid under the laws of the Republic of India and in accordance with this Agreement on:

- (i) dividends not dealt with in sub-paragraph (a);
- (ii) interest;
- (iii) royalties and fees for technical services;
- (iv) income in the meaning of paragraph 4 of Article 13;
- (v) directors' fees;
- (vi) income of artistes and sportspersons

- (c) For the purpose of credit referred to in letter (ii) of subparagraph (b) the Indian tax shall be deemed to be 10 per cent of the gross amount of the interest, if the In-

dian tax is reduced to a lower rate or totally waived according to domestic law, irrespective of the amount of tax actually paid.

- (d) The provisions of sub-paragraph (c) shall apply for the first 12 fiscal years for which this Agreement is effective.
- (e) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) items of income dealt with in Articles 7 and 10 and gains derived from the alienation of the business property of a permanent establishment as well as the items of capital underlying such income shall be exempted from German tax only if the resident of the Federal Republic of Germany can prove that the receipts of the permanent establishment or company are derived exclusively or almost exclusively from active operations.

In the case of items of income dealt with in Article 10 and the items of capital underlying such income the exemption shall apply even if the dividends are derived from holdings in other companies being residents of the Republic of India which carry on active operations and in which the company which last made a distribution has a holding of more than 25 per cent.

Active operations are the following: producing or selling goods or merchandise, giving technical advice or rendering engineering services, or doing banking or insurance business, within the Republic of India.

If this is not proved, only the credit procedure as per sub-paragraph (b) shall apply.

(2) Tax shall be determined in the case of a resident of the Republic of India as follows :

Where a resident of the Republic of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Federal Republic of Germany, the Republic of India shall allow as a deduction from the tax on such income of that resident an amount equal to the income tax paid in the Federal Republic of Germany, whether directly or by deduction, and as a deduction from the tax on such capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in the Federal Republic of Germany. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in the Federal Republic of Germany.

(3) The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income and capital in the respective Contracting State except where express provision to the contrary is made in this Agreement.

Article 24

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more bur-

densome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

(2) The taxation of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Agreement. Further this provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which it grants only to its own residents.

(3) Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned state. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

Article 25

Mutual Agreement Procedure

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from

the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Agreement.

(4) The competent authorities of the Contracting States may establish by mutual agreement the mode of application of the provisions of this Agreement regarding the exemption or reduction of taxes.

(5) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of Information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such Information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or profes-

sional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (order public).

Article 27

Diplomatic and Consular Privileges

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of a diplomatic mission, a consular post or an international organisation under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

Entry Into Force

(1) The Governments of the Contracting States shall notify to each other that the legal requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

(2) This Agreement shall enter into force one month after receipt of the latter of the notifications referred to in paragraph 1 and shall have effect:

- (a) In the Federal Republic of Germany
 - (i) in the case of other taxes withheld at source on dividends, interest, royalties and fees for technical services, in respect of amounts paid on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force;
 - (ii) in the case of other taxes, in respect of taxes levied for periods beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force;
- (b) in the Republic of India
 - (i) in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which this Agreement enters into force;
 - (ii) in respect of capital which is held on the last day of any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which this Agreement enters into force.

(3) Upon the entry into force of this Agreement the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of India for the Avoidance of Double Taxation of Income signed on 18th March 1959 and the Protocol amending the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of India for the Avoidance of Double Taxation of Income signed on 28th June 1984 along with the Exchange of Notes of the same date shall expire and shall cease to have effect as from the date on which the provisions of this Agreement commence to have effect.

Article 29 Termination

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect:

- (a) In the Federal Republic of Germany
 - (i) in the case of taxes withheld at source on dividends, interest, royalties and fees for technical services, in respect of amounts paid on or after the first day of January of the calendar year next following that in which notice of termination is given;
 - (ii) in the case of other taxes, in respect of taxes levied for periods beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which notice of termination is given;
- (b) in the Republic of India
 - (i) in respect of income arising any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which the notice of termination is given;
 - (ii) in respect of capital which is held on the last day of any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which the notice of termination is given;

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done at Bonn on June 19th, 1995 in two originals, each in the German, Hindi and English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretation of the German and the Hindi text the English text shall prevail.

For the Republic of India

Sd/(Illegible)

For the Federal Republic of Germany

[Notification No. 10235/96-FTD
(F.No.500/47/90-FTD) Dated 29/11/96

N.P. SAHNI, Jt. Secy.

Protocol

The Republic of India

and

the Federal Republic of Germany

have agreed at the signing at Bonn on June 19th, 1995 of the Agreement between the two States for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capi-

tal upon the following provisions which shall form an integral part of the said Agreement.

1. With reference to Article 7:

- (a) In the determination of the profits of a building site or construction, assembly or installation project there shall be attributed to that permanent establishment in the Contracting State in which the permanent establishment is situated only the profits resulting from the activities of the permanent establishment as such. If machinery or equipment is delivered from the head office or another permanent establishment of the enterprise (situated outside that contracting State) or a third person (situated outside that Contracting State) in connection with those activities or independently therefrom there shall not be attributed to the profits of the building site or construction, assembly or installation project the value of such deliveries.
- (b) Income derived by a resident of a Contracting State from planning, project, construction or research activities as well as income from technical services exercised in that State in connection with a permanent establishment situated in the other Contracting State, shall not be attributed to that permanent establishment.
- (c) In respect of paragraph 1 of Article 7, profits derived from the sale of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold, or from other business activities of the same or similar kind as those effected, through that permanent establishment, may be considered attributable to that permanent establishment if it is proved that :
 - (i) this transaction has been resorted to in order to avoid taxation in the Contracting State where the permanent establishment is situated, and
 - (ii) the permanent establishment in any way was involved in this transaction.
- (d) It is understood that the deductions in respect of the head office expenses as referred to in paragraph 3 of Article 7 shall in no case be less than those allowable under the Indian Income Tax Act as on the date of entry into force of this Agreement.
- (e) No deduction shall be allowed in respect of amounts paid or charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of :
 - (i) royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights;
 - (ii) commission for specific services performed or for management; and
 - (iii) interest on moneys lent to the permanent establishment except in case of a banking institution.

2. With reference to Article 8:

For the purposes of Article 8 income from the operation of ships includes income derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

3. With reference to Article 10:

For the purpose of taxation in the Federal Republic of Germany, the term dividends includes income derived by a sleeping partner ("stiller Gesellschafter") from his participation as such and distributions on certificates of an investment fund or investment trust. For the purpose of taxation in the Republic of India any income of a similar kind will be treated a like.

4. With reference to Articles 10 and 11:

Notwithstanding the provisions of these Articles, dividends and interest may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State.

- (a) if they are derived from rights or debt claims carrying a right to participate in profits (including income derived by a sleeping partner from his participation as such, from a "partiarisches Darlehen" and from "Gewinnobligationen" within the meaning of the tax law of the Federal Republic of Germany) and
- (b) under the condition that they are deductible in the determination of profits of the debtor of such income.

5. With reference to Article 13:

In view of the position confirmed on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany that the Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) is wholly owned by the Government of the Federal Republic of Germany and is exempted from paying income tax in Germany, it is agreed that the long term capital gains arising to the DEG due to alienation of shares in Indian companies will be exempt from taxation in India.

6. With reference to Article 23:

- (a) The exemption provided for in sub-paragraph (a) of paragraph 1 of Article 23 is granted irrespective of whether the income or capital concerned is effectively taxed in the Republic of India or not.
- (b) Where a company being a resident of the Federal Republic of Germany distributes incomes derived from sources within the Republic of India paragraph 1 of Article 23 shall not preclude the compensatory imposition of corporation tax on such distributions in accordance with the provisions of German tax law.
- (c) The Federal Republic of Germany shall avoid double taxation by a tax credit as provided for in paragraph 1 (b) of Article 23, and not by a tax exemption under paragraph 1 (a) of Article 23,

- (aa) if in the Contracting States' income is placed under differing provisions of the Agreement or attributed to different persons (other than under Article 9) and this conflict cannot be settled by procedure pursuant to Article 25 and

- (i) if as a result of such placement or attribution the relevant income would be subject to double taxation; or
- (ii) if as a result of such placement or attribution the relevant income would remain untaxed or be subject only to inappropriately reduced taxation in the Republic of India and would (but for the application of this paragraph) remain exempt from tax in the Federal Republic of Germany; or

- (bb) if the Federal Republic of Germany has, after due consultation and subject to the limitations of its internal law, notified the Republic of India through diplomatic channels of other items of income to which it intends to apply this paragraph in order to prevent the exemption of income from taxation in both Contracting States or other arrangements for the improper use of the Agreement.

In the case of a notification under sub-paragraph (bb) the Republic of India may, subject to notification through diplomatic channels, characterise such income under the Agreement consistently with the characterisation of that income by the Federal Republic of Germany. A notification made under this paragraph shall have effect only from the first day of the calendar year following the year in which it was transmitted and any legal prerequisites under the domestic law of the notifying State for giving it effect have been fulfilled.

7. With reference to Article 26

- (a) It is also understood that in relation to the Agreement, the term "information" shall include documents. It is further understood that the German tax law provides for the transmission of information in terms of paragraph 3 of Article 117 of the Fiscal Code (Abgabenordnung) - upon request - and it would be possible to furnish information to the competent authority in the Republic of India under these provisions irrespective of this Article.
- (b) If personal data is exchanged under this Article, the following additional provisions shall apply subject to the domestic laws of each Contracting State:
 - (i) The data supplying Contracting States shall be responsible for the accuracy of the data they supply. If it emerges that inaccurate data or data which should not have been supplied have been communicated, the receiving State shall be notified of this without delay. That State shall be obliged to correct or destroy said data;

- (ii) The Contracting States shall be obliged to keep official records of the transmission and receipt of personal data;
- (iii) The Contracting States shall be obliged to take effective measures to protect the personal data communicated against unauthorised access, unauthorised alteration and unauthorised disclosure;
- (iv) Upon application the person concerned shall be informed of the information stored about him and of the use planned to be made of it. There shall be no obligation to give this information if on balance it appears that the public interest in withholding it outweighs the interest of the person concerned in receiving it. In all other respects the right of the person concerned to be informed of the data stored about him shall be gov-

erned by the domestic law of the Contracting State in whose sovereign territory the application for the information is made.

Done at Bonn on June 19th 1995 in two originals, each in the German, Hindi and English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretation of the German and the Hindi text the English text shall prevail.

For the Republic of India

For the Federal Republic of Germany

[Notification No. 10235/96-FTD./
F.No. 500/47/90-FTD.]
N.P. SAHNI, Jt. Secy.

